इकाई 6 समाजवादी विश्व-II

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 पृष्ठभूमि

6.3 योजना और औद्योगीकरण

- 6.3.1 प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1929-33
- 6.3.2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1933-37
- 6.3.3 नियोजित औद्योगीकरण के परिणाम
- 6.3.4 तृतीय पंचवर्षीय योजना, 1938-41

6.4 कृषि का सामूहिकीकरण

- 6.4.1 नई आर्थिक नीति में कृषि की कमज़ोरियां
- 6.4.2 अनाज का उत्पादन और विपणन
- 6.4.3 1927-28 का वसूली संकट
- 6.4.4 किसानों द्वारा सामूहिक खेती का प्रतिरोध
- 6.4.5 सामूहिकीकरण की प्रकृति

6.5 आतंक और शुद्धीकरण

- 6.5.1 चार मुकदमे
- 6.5.2 शुद्धीकरण और साम्यवादी दल
- 6.5.3 शुद्धीकरण और सेना
- 6.5.4 शुद्धीकरण और सोवियत समाज

6.6 सारांश

6.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.0 उद्देश्य

पिछली इकाई के विवरण को इस इकाई में भी जारी रखा गया है, इसमें सोवियत रूस की चर्चा को आगे बढ़ाया गया है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः

- 1930 के दशक में सोवियत रूस में प्रमुख राजनैतिक और आर्थिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे;
- 1929 के बाद शुरू किए गए नियोजित औद्योगीकरण की प्रकृति का उल्लेख कर सकेंगे;
- कृषि के सामूहिकीकरण और रूसी किसानों पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाल सकेंगे; और
- 1930 के दशक के राजनैतिक कारकों से परिचित हो सकेंगे जिसके चलते आतंक और शुद्धीकरण की शुरुआत हुई।

6.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में रूसी क्रांति और क्रांति के बाद की प्रमुख घटनाओं की चर्चा की गई थी। उसमें आपने क्रांति के बाद स्थापित हुए युद्ध साम्यवाद की जानकारी प्राप्त की। 1921 के आसपास युद्ध साम्यवाद का स्थान नई आर्थिक नीति ने ले लिया। 1928 के आसपास नई आर्थिक नीति के स्थान पर सोवियत रूस में उद्योग और कृषि का योजनाबद्ध ढंग से विकास शुरू हुआ। इस इकाई में रूसी अर्थव्यवस्था के योजनाबद्ध चरण की कहानी कही गई है। सबसे पहले योजनाबद्ध या नियोजित अर्थव्यवस्था का अर्थ समझाया गया है। इसके बाद 1930 के दशक की तीन प्रमुख घटनाओं की चर्चा की गई है; यह थीं नियोजित औद्योगीकरण, कृषि का सामूहिकीकरण और 1930 के दशक का शुद्धीकरण। इन तीनों ने सोवियत रूस के इतिहास को काफी प्रभावित किया।

6.2 पृष्ठभूमि

1926 और 1941 के बीच के कम समय में औद्योगीकरण का विस्तार तेज़ी से हुआ परंतु यह रूस में आधुनिक औद्योगीकरण की शुरुआत नहीं थी। 1890 के दशक में जार के मंत्री एस. आई. विट के प्रयास से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। प्रथम विश्वयुद्ध के पहले औद्योगीकरण में उछाल आया, शस्त्र निर्माण और अभियांत्रिकी उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। परंतु युद्ध के दौरान इतना तेज और व्यापक विकास हुआ कि 1930 के दशक तक सोवियत रूस एक बड़ी औद्योगिक शक्ति बन गया। द्वितीय विश्वयुद्ध की तबाही से उबरने के बाद महाशक्ति के रूप में उभरने का यही आधार बना। 1926 से 1941 के दौरान हुआ सोवियत आर्थिक विकास दुनिया का पहला विस्तृत राज्य द्वार नियोजन था और इस प्रकार विश्व औद्योगीकरण के इतिहास में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है।

सोवियत सरकार में इस बात को लेकर कोई असहमति नहीं थी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और समाज का निर्माण आधुनिकीकरण और उद्योग के विस्तार से किया जा सकता है। इससे दुनिया के एकमात्र समाजवादी देश (1949 तक) को विरोधी पूंजीवादी दुनिया का सामना करने की ताकत मिलेगी। इस बात पर भी कोई असहमति नहीं थी कि औद्योगीकरण कृषि के आधुनिकीकरण के बिना आगे नहीं बढ़ सकता था। कृषि की उत्पादकता बढ़ाए बिना औद्योगिक मज़दूरों की बढ़ती संख्या को एक बेहतर जीवन स्तर देना संभव नहीं था और प्रौद्योगिकी तथा मशीन के आयात के भुगतान के लिए अनाज़ का निर्यात ज़रूरी था तथा युद्ध और अकाल के समय के लिए अनाज़ का पर्याप्त भंडार सुरक्षित रखना भी ज़रूरी था।

सोवियत बोल्शेविकों जैसे मार्क्सवादी सदैव अर्थव्यवस्था के 'योजना' में विश्वास रखते थे। मार्क्स ने कहा था कि एक समाजवादी समाज बाज़ार की ताकतों के निरंकुश नियंत्रण से या पूंजीपति वर्ग के अधिकतम मुनाफा कमाने के आत्म हित नियंत्रण से मुक्त होगा। इसके स्थान पर समाजवादी समाज लोगों की वास्तविक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों पर सीधा नियंत्रण रखेगा और योजनाबद्ध ढ़ंग से उत्पादन करेगा।

6.3 योजना और औद्योगीकरण

1920 से ही दस से पन्द्रह साल की दीर्घकालिक योजना का विचार पनप रहा था। 1925 के आंकड़ों से वार्षिक नियंत्रण और अनुमान के लिए वार्षिक योजना का पूर्वानुमान तैयार किया जा रहा था। 1926 से राज्य योजना आयोग (गौसप्लान) और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था परिषद (VSNKH) ने भावी पंचवर्षीय योजना के कई प्रारूप बना डाले थे। इसका दोहरा महत्व

था। इससे औद्योगीकरण के प्रति प्रतिबद्धता की शुरुआत हुई और एक विस्तृत योजना के द्वारा राज्य के नेतृत्व में विकास हुआ। दूसरे, इसे कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षाकृत कम समय की योजना बनाई गई।

1926 तक अधिकांश सोवियत उद्योग फिर से 1913 के उत्पादन स्तर तक पहुंच गए और कुछ उद्योगों ने यह स्तर भी पार कर लिया। इसके बाद सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में निम्नलिखित पक्षों पर बल दिया :

- समाजवादी ढर्रे पर तीव्र औद्योगीकरण; और
- ऐसी औद्योगीकरण पद्धति जिसमें बड़े पैमाने के भारी उद्योग और विर्निमाण का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर वर्चस्व होगा।

सोवियत रूस में एक देश में समाजवाद का निर्माण हो रहा था और वह चारों ओर से शत्रुतापूर्ण पूंजीवादी विश्व से घिरा हुआ था; इसलिए सोवियत उद्योग का इस अर्थ में आत्म निर्भर होना ज़रूरी था कि किसी बड़े उत्पाद के लिए उसे पूंजीवादी देशों पर आश्रित न रहना पड़े। कम से कम समय में पूंजीवादी देशों से आगे बढ़ना एक प्रमुख उद्देश्य था।

इसके लिए पूंजी, उपकरण, रसायनों और अन्य विकसित उत्पादों के उत्पादन की क्षमता हासिल करना आवश्यक था जिसका जार युग से विरासत में प्राप्त उद्योगों में अभाव था। आत्मनिर्भरता के लिए भी सोवियत उद्योग को अत्यधिक विकसित प्रौद्योगिकी को हासिल करना अनिवार्य था। इस बात पर भी सहमति थी कि उत्तर पश्चिम, मध्य यूरोपीय रूस और यूक्रेन जैसे आधुनिक उद्योग के परम्परागत केंद्र में नए कारखाने नहीं लगाए जाएंगे बल्कि इनकी स्थापना उराल और साइबेरिया तथा पिछड़े मध्य एशिया में की जाएगी। प्रतिरक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोहे और इस्पात निर्माण, अभियांत्रिकी और अस्त्र बनाने वाले उद्योगों की स्थापना सोवियत रूस के उन क्षेत्रों में की गई जहां अपेक्षाकृत आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता था।

6.3.1 प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1929-33

चूंकि 1928 औद्योगिक वृद्धि के लिए एक सफल वर्ष था अतः पुराने योजना लक्ष्यों को संशोधित कर आगे बढ़ाया गया। किसी को भी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्य पद्धति को समझने की सांख्यिकी सूचना या सैद्धांतिक समझ नहीं थी। जैसे-जैसे नई आर्थिक नीति के तहत बाज़ार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वृद्धि की दर को लेकर प्रमुख सोवियत नेता अधीर होते गये वैसे-वैसे प्रमुख सतर्क योजना का स्थान राजनीति की माँगों ने ले लिया। आर्थिक रूप से व्यावहारिक लक्ष्यों के सावधानीपूर्वक तैयार किये गये अनुमानों के अनुसार चलने वाली नियोजित अर्थव्यवस्था के स्थान पर एक 'आदेशात्मक' अर्थव्यवस्था का आगमन हुआ जो राजनैतिक आदेशों और सरकार की प्राथमिकताओं से निर्देशित होती थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में लोहे और इस्पात पर अधिक ध्यान दिया गया परंतु ट्रैक्टर्स संयंत्रों को भी उच्च प्राथमिकता दी गई। विदेश से मशीन आयात की निर्भरता को समाप्त करने के लिए मशीन और औज़ार उद्योग का तेज़ी से विकास हुआ। स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत नेतृत्व कुछ पूर्वाग्रहों से युक्त था जिसका प्रभाव योजना पर पड़ा जो संतुलित और यथार्थवादी आर्थिक विकास की प्रक्रिया के रूप में योजना के लिए हानिकारक था। उनका मानना था कि बड़े-बड़े औद्योगिक परिसरों के निर्माण से ही औद्योगिक विकास हो सकता था। इसमें ऐसे बड़े औद्योगिक परिसरों के निर्माण की मांग की गई जिन्हें चलाने या बनाने के लिए संसाधन मौजूद नहीं था। इसको *गिगंतोमेनिया* (विशालता का उन्माद) कहा जा सकता है। परिणामस्वरूप इसे बनाने में ज़्यादा समय लगा और बार-बार काम रुका तथा कुछ काम अधूरे भी छूट गए। आकार के साथ-साथ सब कुछ जल्दी में भी करने का आग्रह

था। इसलिए इस समय 'रफ्तार सबका निर्णय करती है', का नारा दिया गया। उसे स्पष्ट करने के लिए 1929 के मध्य में औपचारिक रूप से प्रथम पंचवर्षीय योजना अपनाई गई; इसकी शुरुआत अक्टूबर 1928 से मानी गई और अन्ततः जनवरी 1933 में इसकी समाप्ति की घोषणा की गई। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना पांच वर्षों में ही नहीं बल्कि सवा चार वर्षों में ही सम्पन्न हो गई।

मात्रात्मक रूप में यानि उत्पादन की मात्रा के रूप में योजना के उद्देश्य निर्धारित किए गए। योजना में उत्पादन बढ़ाने के लिए वास्तविक सामग्री संसाधनों की उपलब्धता का बहुत ही अस्पष्ट संकेत दिया जाता था। उद्योग से यह उम्मीद की जाती थी कि वह केवल योजना के लक्ष्यों को ही पूरा न करे बल्कि उससे आगे भी बढ़ जाए। योजना का उद्देश्य संसाधन आवंटित करना या संतुलित मांगों की पूर्ति करना नहीं था बल्कि अर्थव्यवस्था को हड़बड़ी कर आगे बढ़ाना था। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में तेज़ी से कमी आई और नई मशीने महंगी होने के बावजूद काफी खराब किस्म की थीं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के मिले जुले परिणाम सामने आए। हालांकि धातु उत्पादन बढ़ाने के लिए सब कुछ त्याग दिया गया परंतु कोयला, तेल, कच्चा लोहा और लौहपिंड का उत्पादन उम्मीद से काफी कम हुआ। मशीनरी और धातु कर्म में निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा उत्पादन हुआ परंतु ऐसा भी अंशतः आंकड़ों के सांख्यिकीय हेर-फेर से हुआ। 1940 में इस्पात उत्पादन, 1951 में बिजली उत्पादन और 1955 में तेल उत्पादन का लक्ष्य पूरा हुआ। भारी उद्योग में तेज़ी से विकास के लिए उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि और थोड़े समय के लिए सैन्य शक्ति की भी बलि दे दी गई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य ने संभवतः आपूर्ति और वितरण के संगठन का सर्वाधिक कठिन कार्य किया। एक दशक पूर्व गृह युद्ध के दौरान ऐसा करने का असफल प्रयत्न किया गया था, इसलिए राज्य ने शहरी अर्थव्यवस्था, वितरण और व्यापार का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इस बार 1980 के दशक तक यह स्थिति बनी रही। 1920 के दशक के अंत से निजी उत्पादन और व्यापार में कटौती की जाने लगी। नई आर्थिक योजना के लोगों (निजी व्यापारियों) के खिलाफ तेज़ी से कार्यवाई की गई। उनके खिलाफ अखबारों में दुष्प्रचार किया गया, कानूनी और वित्तीय स्तर पर उन्हें परेशान किया गया और 1928-29 में 'सट्टेबाजी' के लिए कई निजी उद्यमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1930 के दशक के आरंभ में छोटे कारीगरों और दुकानदारों से भी उनका व्यापार छीन लिया गया था या उन्हें राज्य नियंत्रित सहकारी समितियों में शामिल होने के लिए बाध्य किया गया। अभी तक व्यापार और वितरण का वैकल्पिक ढ़ांचा तैयार नहीं हुआ था। कृषि की सामूहिकीकरण के साथ ही नई आर्थिक नीति की मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य और निजी क्षेत्र मिलजुलकर काम करते थे पूर्णतया समाप्त हो गई।

6.3.2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1933-37

फरवरी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इसके तीन निर्देशक सिद्धांत इस प्रकार थे:

- सुदृढ़ीकरण;
- तकनीक की विशेज्ञता; और
- जीवन स्तर सुधारना।

इस योजना में तर्कसंगत योजना का सिद्धांत प्राप्ति के पास आया। अधिक संतुलित और वास्तविक उत्पादक लक्ष्य रखे गए। उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाना और निपुणता हासिल करना मुख्य उद्देश्य हो गया।

इस योजना में उत्पादक वस्तुओं की अपेक्षा उपभोक्ता वस्तुओं में अधिक निवेश और उत्पादन वृद्धि पर बल दिया गया। नगद मज़दूरी में वृद्धि और खुदरा वस्तुओं की कीमतों में कमी आने से शहरों में रहने वाले मज़दूरों के वास्तविक वेतन के दुगने होने की उम्मीद की गई।

दूसरी योजना के दौरान बड़ी संख्या में औद्योगिक उद्यम स्थापित किए गए। इसका मतलब यह हुआ कि 1927 तक 80% औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन नए या पूरी तरह पुनर्निर्मित उद्यमों में होने लगा। इस योजना के दौरान भारी उद्योगों के उद्देश्य लगभग पूरे कर लिए गए और मशीनों तथा बिजली के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई।

हालांकि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन उम्मीद से कम बढ़ा और 1928 के मुकाबले 1937 में ज़रूरी घरेलू वस्तुओं का प्रति व्यक्ति उपभोग कम रहा। मैग्निटोगोर्सक, कुजनेस्क और झापोरोभेय में धातुकर्म का कार्य पूर्ण होने से सोवियत रूस की विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम हो गई, भुगतान संतुलन का भार कम हुआ और पुराने ऋणों को चुकाने में सहूलियत हुई। 1937 तक आधाभूत मशीनें और प्रतिरक्षा सामान सोवियत रूस में बनाए जाने लगे। इस योजना के दौरान मध्य एशिया और कज़ाकिस्तान में पिछड़े राष्ट्रीय गणतंत्रों को विकसित करने का प्रयत्न किया गया। हालांकि सीमित संसाधनों के उपयोग को देखते हुए आर्थिक दृष्टि से यह सबसे अच्छा तरीका नहीं था।

6.3.3 नियोजित औद्योगीकरण के परिणाम

1928 के बाद के दशक में विश्व अर्थव्यवस्था के इतिहास में सोवियत उद्योगों का विकास अभूतपूर्व दर और गति से हुआ। सोवियत सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1928 की तुलना में 1937 में औद्योगिक उत्पादन 446% बढ़ गया, रूढ़िवादी पश्चिमी आकलन के अनुसार 239% की वृद्धि हुई। इसी प्रकार सोवियत आंकड़ों के अनुसार वृद्धि दर 18% और पश्चिमी आंकड़ों के अनुसार यह वृद्धि 10-5% थी।

सोवियत सरकारी आंकड़ों के अनुसार विश्व उत्पादन में सोवियत रूस का हिस्सा जहां 1913 में 2-6% और 1929 में 3-7% था वहीं 1937 में यह बढ़कर 13-7% हो गया। सोवियत रूस एक तरफ ऊँचाइयों को छू रहा था जबकि पश्चिमी देश भयंकर मंदी और व्यापक बेरोज़गारी से गुज़र रहे थे। 1928 में सोवियत रूस का औद्योगिक उत्पादन जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन जैसे द्वितीय श्रेणी के पूंजीवादी देशों के स्तर का था। 1937 तक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका इससे आगे रह गया। तब तक प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के मुकाबले सोवियत संघ की उत्पादन शक्ति दोगुनी हो चुकी थी। सोवियत उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग में परिणत हो गया: 1913 में सोवियत औद्योगिक उत्पादन का एक तिहाई हिस्सा लघु उद्योगों में होता था जबकि 1937 तक यह अनुपात गिरकर मात्र 6% रह गया।

पश्चिम से मशीनों और जानकारियों का भारी मात्रा में निर्यात कर प्रमुख नए उद्योगों की स्थापना की गई। 1937 तक आते-आते सोवियत संघ बड़ी मात्रा में लोहा और इस्पात तथा बिजली के उपकरण, ट्रैक्टर, फसल कटाई के उपकरण, टैंक और हवाई जहाज़ के साथ-साथ सभी प्रकार के मशीन उपकरण बनाने लगा; और सभी उद्योगों में प्रौद्योगिकी का स्तर ऊपर उठा। श्रम उत्पादकता (कार्यरत प्रति व्यक्ति उत्पादन) में प्रतिवर्ष औसतन 6% की वृद्धि हुई। उन्नीसवीं शताब्दी में किसी भी समय ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका में इतनी तेज़ी से वृद्धि नहीं हुई थी।

6.3.4 तृतीय पंचवर्षीय योजना, 1938-41

1938 और 1941 के बीच जर्मनों ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। तीसरी पंचवर्षीय योजना का साढ़े तीन वर्ष इसी में चला गया। 1 जून 1941 में द्वितीय विश्वयुद्ध से योजना

में बाधा पड़ी और यह कभी पूरा नहीं हो पायी। इस समय भी पांच वर्षों के दौरान प्रभावी प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया : औद्योगिक उत्पादन में 92, इस्पात में 58, मशीन और अभियांत्रिकी में 129। एक बार फिर उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई।

बोध प्रश्न 1

1) योजनाबद्ध औद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं? पांच पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं ने रूसी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया? दस पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

6.4 कृषि का सामूहिकीकरण

पिछले भाग में औद्योगीकरण पर बातचीत करने के क्रम में हमने देखा कि सोवियत नेतृत्व ने सफलतापूर्वक अपने देश को विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिणत कर दिया। हालांकि कृषि में प्रमुख बदलाव लाए बिना औद्योगीकरण संभव नहीं था। गृहयुद्ध के बाद उत्पाद में हुई पर्याप्त वृद्धि के बावजूद प्रति हेक्टेयर उत्पादन और श्रम उत्पादकता दोनों ही दृष्टियों से सोवियत कृषि किसी भी प्रमुख यूरोपीय देश से बहुत पिछड़ा हुआ था। अधिकांश उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर राज्य ने उद्योग के एक बड़े हिस्से पर सफलतापूर्वक अपना नियंत्रण मज़बूत किया परंतु कृषि क्षेत्र में निजी कृषक खेतों की मौजूदगी के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादन और विपणन निर्णयों पर राज्य का नियंत्रण नहीं था और कृषि केंद्रीय योजना और नियंत्रण के दायरे से बाहर थीं।

बोल्शेविकों का मानना था कि पूंजीवादी कृषि के निजी खेतों की जगह सामाजिक या सामूहिक कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बड़े खेतों में अधिक उत्पादन संभव होगा क्योंकि इनमें मशीनों और उर्वरकों का इस्तेमाल अच्छे ढंग से किया जा सकता था। इनसे औद्योगीकरण के लिए कृषि अधिशेष का निर्माण होगा। इसके अलावा उत्पादन संसाधनों को एक बड़े खेत में एकत्र करके लगाने से किसानों के बीच सम्पत्ति की असमानता भी दूर होगी। बोल्शेविकों का मानना था कि किसानों को सामूहिक और समाजवादी खेती के लिए राजी करने में काफी वक्त लगेगा और यह दुरूह प्रक्रिया होगी। अपने एक लेख 'सहयोग की ओर' में लेनिन ने लिखा था कि सरकार को किसानों को इस बात के लिए राजी करने का प्रयास करना चाहिए कि वे अपने निजी खेत छोड़ दें और सामूहिक खेतों

में मिल जुलकर काम करें। इसके लिए किसानों को आधुनिक उपकरण, ऋण और कृषि संबंधी सभी प्रकार की सहायता दी जानी थी।

नई आर्थिक नीति में विकसित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल नहीं दिया गया जिससे कि किसानों को सामूहिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जब तक सोवियत रूस में ट्रैक्टर आए अधिकांश बोल्शेविकों का मानना था कि समाजवादी कृषि की तैयारी के लिए कई कदम उठाने होंगे। किसानों को धीरे-धीरे सामूहिक खेती की ओर बढ़ना होगा। इसके लिए पहले उपभोक्ता वस्तुओं को बेचने, कृषि उत्पादों के विपणन और आपूर्ति के लिए सहकारी समितियां बनानी होगी और मशीन, बीज, भूमि सुधार, निर्माण के लिए सहकारी समितियों को ऋण उपलब्ध कराना होगा और अंत में उन्हें सामूहिक खेती के लिए प्रेरित करना होगा।

1920 के दशक में कृषिशास्त्रियों और भूमि चकबंदी विशेषज्ञों को कुछ किसानों को अपनी भू-जोतों का सुदृढ़ीकरण करके सामूहिक खेती के लिए प्रेरित करने में थोड़ी सफलता मिली। परंतु अभी काफी कम किसान इस प्रकार की खेती के लिए राजी थे। यह सोचकर कि सहकारी समितियों के निर्माण से किसानों में सामूहिकीकरण की भावना बढ़ेगी, सोवियत राज्य ने सहकारी समितियों को आसान ऋण, कर छूट और दुर्लभ उत्पादित वस्तुओं की आपूर्ति में प्राथमिकता देने का वादा किया। परंतु सहकारी समितियां भी बहुत कम संख्या में किसानों को आकर्षित करने में बहुत सफल नहीं रही।

ग्रामीण पूंजीवाद के प्रसार से किसानों के बीच बढता विभेदीकरण सोवियत नेतृत्व के लिए चिंता का विषय था। ग्रामीण पूंजीवाद से केवल अमीर कृषकों या कुलक को ही फायदा होना था जिसकी कीमत पूरे कृषक समुदाय को चुकानी पड़ रही थी। तीन तरीकों से किसानों के बीच विभेदीकरण बढ़ रहा था, जैसे पट्टे पर ज़मीन देना; ऋण, पशु, उपकरण और मशीन की उपलब्धता; और मज़दूरों को मज़दूरी पर रखना। कुलक को परिभाषित करने के मानदंड बनाये गये थे : जो मज़दूर रखते थे, खरीदकर या पट्टे पर ज़मीन प्राप्त करते थे, जिनके पास बड़ी मिल्कियत थी और जो कृषि के उत्पादन के साधनों को पट्टे पर उठाया करते थे तथा जिनकी वाणिज्यिक और वित्तीय कारोबार से आमदनी थी। परंतु कभी भी कुलक की स्पष्ट और सुनिश्चित परिभाषा प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

6.4.1 नई आर्थिक नीति में कृषि की कमज़ोरियां

नई आर्थिक नीति के दौरान किसानों के खेती करने का तरीका और प्रौद्योगिकी काफी पिछड़ी हुई थी। 1927 में, खेती योग्य ज़मीन का 88 प्रतिशत हिस्सा छोटे-छोटे खेतों में विभक्त था और पांच प्रतिशत से कम खेतों की पूरी तरह या आंशिक रूप से बाड़बंदी की गई थी। खेतों के छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटे होने के कारण खेती की आधुनिक तकनीकों और बेहतर उपकरणों का उपयोग संभव नहीं था। तीन खेतों में अदल बदल कर फसल उगाने की व्यवस्था थी। खेतों में दो फसलें उगाई जाती थीं; और पहले चक्र में शरत ऋतु में राई, गेहूं तथा दूसरे चक्र में वसंत ऋतु में गेहूं या अन्य फसल बोई जाती थी और तीसरे चक्र में खेत परती छोड़ दिया जाता था; इसे तीन चक्रीय खेती व्यवस्था के रूप में जाना जाता था और सोवियत संघ में यही पद्धति सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। इसके अलावा इससे भी आदिम दो खेतों पर खेती करने या स्थानांतरित खेती प्रथा भी मौजूद थी। इसके परिणामस्वरूप एक तिहाई हिस्सा हमेशा परती पड़ा रहता था।

सरकार जल्द से जल्द प्रौद्योगिकी में सुधार लाना चाहती थी परंतु यह इतना आसान नहीं था। 1927 में रूसी संघ के लगभग एक चौथाई किसानों के पास घोड़ा या बैल नहीं था और एक तिहाई किसानों के पास खेत जोतने के उपकरण नहीं थे। अधिकांश किसानों के

पास बिना घोड़े के उपयोग किए जानेवाले उपकरण थे। मशीनों का इस्तेमाल मुख्य तौर पर अनाज उत्पादन करने वाले प्रमुख देहाती क्षेत्रों में ही होता था।

6.4.2 अनाज का उत्पादन और विपणन

हालांकि 1920 के दशक तक अनाज का उत्पादन युद्ध पूर्व स्तर तक पहुंच गया था परंतु 1920 के दशक में प्रथम विश्व युद्ध के पहले की तुलना में अनाज का विपणन काफी कम हुआ था। ऐसा अंशतः गांव की जनसंख्या में वृद्धि के कारण हुआ 1913 और 1926 के बीच 60 लाख आबादी बढ़ी जबकि 1913 की तुलना में इस समय प्रति व्यक्ति अनाज उत्पादन में 16 प्रतिशत की कमी आई।

एक प्रमुख समस्या यह थी कि कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए एक से अधिक बाज़ार थे। अन्न और अन्य फसलों के बाज़ारों में राज्य और सहकारी प्रयत्नों का हिस्सा काफी कम था और निजी बाज़ार तितर बितर थे परंतु उनमें में उत्पादकों को लाभ के कई विकल्प उपलब्ध थे। राज्य खरीद अभिकरणों की अपेक्षा किसानों के लिए निजी बाज़ार में अनाज बेचना ज़्यादा लाभप्रद था क्योंकि यहां ऊँची कीमतें मिलती थीं। निजी व्यापारियों से किसानों को अपनी ओर खींचना राज्य की एक बहुत बड़ी समस्या थी।

व्यापार की शर्तें या औद्योगिक खुदरा मूल्यों और राज्य के कृषि खरीद मूल्य के बीच का संबंध युद्ध पूर्व समय की अपेक्षा किसानों के लिए कम अनुकूल था। अपने उत्पादों के लिए प्रतिकूल मूल्य अनुपात के अलावा युद्ध पूर्व समय की अपेक्षा किसानों की औद्योगिक बस्तुओं तक पहुंच भी कम हो गई। 1920 के पूरे दशक में औद्योगिक वस्तुएं मंहगी, खराब कोटि की और दुर्लभ हो गईं।

राज्य के अनाज का वसूली मूल्य (*झागातोवकि*) इतना कम होता था कि इससे अक्सर उत्पादन की लागत भी नहीं निकल पाती थी। पशुधन उत्पाद और औद्योगिक फसलों का मूल्य किसानों के अधिक अनुकूल था और इससे अनाज वितरण को धक्का पहुंचा।

1917-20 की कृषि क्रांति के बाद गांवों में सामाजिक और आर्थिक संगठनों में हुए परिवर्तन से भी कृषि विपणन में गिरावट आई। बड़ी निजी सम्पदाओं के पुनर्विभाजन से वे कृषि इकाइयां समाप्त हो गईं जो अधिक बाज़ारोन्मुख थीं।

6.4.3 1927-28 का वसूली संकट

1927 की शरद ऋतु की फसल अच्छी होने के बावजूद किसान अपेक्षाकृत कम अनाज बाज़ार में ले गए और सरकार इतना अनाज न खरीद सकी जिससे शहर के लोगों और सेना का भरणपोषण तथा मशीनों के आयात के लिए अनाज का निर्यात किया जा सके। यदि राज्य निजी बाज़ारों के मूल्यों का मुकाबला करने के लिए अनाज का वसूली मूल्य बढ़ाता तो औद्योगिक विकास के लिए आवंटित राशि में कटोती करनी पड़ती।

1927-28 के दौरान औद्योगिक निवेश में हुई तीव्र वृद्धि अक्टूबर 1927 के बाद से होने वाले अनाज संकट का प्रमुख कारक था। भारी उद्योग में निवेश के स्थानांतरण के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की और भी कमी (वस्तु-अकाल) पड़ गई; और अनाज का राज्य वसूली मूल्य कम होने के कारण उनकी लागत और भी मंहगी पड़ती थी।

इस वस्तु-अकाल के जवाब में किसानों ने 'उत्पादन हड़ताल' कर दी और राज्य द्वारा निर्धारित मूल्यों पर सरकार को अनाज बेचने से मना कर दिया। किसानों ने या तो निजी व्यापारियों को ऊँचे दामों पर अनाज बेचा या कर चुकाने के लिए महंगी औद्योगिक फसलों या पशु उत्पादों की बिक्री की।

दूसरे शब्दों में, 1927 का संकट इस अर्थ में कोई आर्थिक संकट नहीं था जिसमें बाज़ार तंत्र बिखर गया हो या उत्पादन क्षमता कम हो गई हो। यह इस बात से स्पष्ट है कि फसल का बड़ा हिस्सा बाज़ार में बेचा गया था पर अक्सर यह निजी व्यापारियों को बेचा गया। किसान अधिशेष उत्पादन के लिए तैयार थे और उनके पास इसकी क्षमता भी थी परंतु वे चाहते थे कि अपने इस अधिशेष से वे औद्योगिक वस्तुएं खरीद सकें।

दिसम्बर 1927 में स्टालिन ने कहा कि किसानों के छोटे-छोटे और बिखरे खेतों को एकत्रित करने का काम धीरे-धीरे शुरू किया जाना चाहिए। इसके लिए ज़ोर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए बल्कि समझाने बुझाने (प्रदर्शन और अनुनय) का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। अगले महीने जनवरी 1928 में उन्होंने कहा कि ''हम कुलक की सनक पर अपने उद्योग को आश्रित नहीं कर सकते; (सामूहिक खेती) पूरे ज़ोर शोर से लागू करनी होगी.... ताकि तीन या चार वर्षों (1931 या 1932 तक) के भीतर वे राज्य के अनाज की ज़रूरत के कम से कम एक तिहाई हिस्से की आपूर्ति कर सकें।''

पार्टी नेतृत्व ने किसानों से सुलह की अपेक्षा टकराव का रास्ता अपनाया। 1928 के आरंभ में बाज़ार बंद कर दिए गए और किसानों तथा व्यापारियों से अनाज ज़ब्त कर लिया गया। जिन लोगों ने अनाज छिपाने या दबाने और आपूर्ति करने में आनाकानी की उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई। इसके परिणामस्वरूप राज्य ने अधिक मात्रा में अनाज वसूली करने में कामयाब रहा।

1928 की गर्मी में पार्टी ने पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक तेजी से ज़्यादा से ज़्यादा अनाज वसूलने का अभियान छेड़ा। नवंबर में प्राधिकारियों ने पांच महीने के भीतर प्रमुख अनाज उत्पादक क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर सामूहिकीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की। 1928 में प्रमुख अनाज उत्पादक क्षेत्रों यूक्रेन और उत्तरी कौकेशस में पैदावाद अच्छी नहीं हुई। देश के दूरस्थ पूर्वी भागों (वोल्गा क्षेत्रों, कज़ाकिस्तान, यूराल और साइबेरिया) में पैदावार सर्वोत्तम हुई परंतु यहां राज्य वसूली तंत्र सबसे कमज़ोर था, सूचना, संचार आदि अधिसंरचना अल्प विकसित थी जो जाड़े में ज़्यादा ही धीमी हो जाती थी। उत्पादित वस्तुओं की कमी से संकट और भी गहरा हो गया। अनाजों के विपणन में तेजी से गिरावट आई और राज्य की एजेन्सियाँ अनाज वसूली में असफल रही। राइ, (एक प्रकार का अनाज जिसका उत्पादन यूरोप में होता है), गेहूं और खाद्यान्नों की कम वसूली के कारण राज्य को अनाज के निर्यात में कटौती करनी पड़ी और शांति काल में भी राशन व्यवस्था पुनः लागू की गई।

सोवियत नेताओं के सामने दो विकल्प मौजूद थे। वे नई आर्थिक नीति, संतुलित औद्योगीकरण, धीरे-धीरे सामूहिकीकरण और किसानों को बाज़ार में अधिक अनाज लाने के लिए कृषि आपूर्ति मूल्य का समायोजन का रास्ता अपना सकते थे; बुखारिन जैसे नेताओं ने इसी प्रकार की नीति की वकालत की थी। इसके अलावा वे ज़ोर जबरदस्ती से सामूहिकीकरण और औद्योगीकरण की नीति अपना सकते थे। स्टालिन ने दूसरा विकल्प चुना।

सामूहिकीरण नीति के अन्तर्गत गांव और जिलों में बड़े-बड़े सामूहिक खेतों का निर्माण करना था। 1929 के वसंत में व्यापक पैमाने पर सामूहिकीकरण अपनाने के लिए कुछ ज़िलों को चुना गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग सभी घरों को सामूहीकृत किया गया। जुलाई के आरंभ तक ऐसे लगभग 11 जिलों को चुना गया।

जिस समय व्यापक पैमाने पर सामूहिकीरण किया गया उसके लिए कोई लम्बी चौड़ी योजना नहीं बनाई गई। यहां तक कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि नीति में भी कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया गया। यह मान लिया गया कि 1934 में चार में से तीन किसानों के खेत अभी भी निजी मिल्कियत में रहेंगे और अनाज की मंडी में आधे से ज़्यादा अनाज

की पूर्ति यही करेंगे। सामूहिकीकरण आरोपित करने का निर्णय तीव्रता से लिया गया। यह न तो पार्टी का निर्णय था और न ही इसमें कानूनी समर्थन था। एक वर्ग के रूप में कुलक को समाप्त करना था और पूरे ग्रामीण इलाकों में सामूहिकीकरण का अभियान चलाना था ताकि गांवों को 'कुलक विहीन' बना देना था। अनाज वसूली अभियान और किसानों को जबरन कोलखोज (सामूहिक खेतों) में मिलाने का कार्यक्रम एक साथ मिला दिया गया।

इस सामूहिक खेतों के बारे में कोई ढ़ांचा या संगठन नहीं बनाया गया; यह भी नहीं तय किया गया कि निर्णय किस प्रकार लिया जाएगा और सदस्यों को भुगतान किस प्रकार किया जाएगा। सात सप्ताहों के भीतर फरवरी 1930 तक लगभग आधे किसान सामूहिकीकरण अभियान की लपेट में आ गए थे।

6.4.4 किसानों द्वारा सामूहिक खेती का प्रतिरोध

किसानों पर जबरदस्ती सामूहिकीकरण थोप दी गई जिसका किसानों ने जमकर निष्क्रिय प्रतिरोध और यत्र-तत्र सशस्त्र विद्रोह भी किया। किसानों ने शासन का सक्रिय विरोध किया और चारों ओर हज़ारों किसानों ने जन प्रदर्शन किए। इसके अलावा 'आंतकवादी गतिविधियां' हुईं जिसमें लोगों को मारा पीटा गया, हत्याएं की गईं, आगजनी और लूटपाट मचाई गई। कुल मिलाकर किसानों का यह प्रतिरोध स्थानीय और मुखर था परंतु यह अर्ध-सैन्य नहीं था। समृद्ध किसानों का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा मुखर था परंतु यह स्पष्ट था कि किसानों का हर वर्ग इससे प्रभावित हुआ था और सामूहिकीकरण के विरोध में सारे किसान शामिल थे।

कोलखोज (सामूहिक खेत) को अपने पशु सौंपने की अपेक्षा कई किसानों ने अपने पशुओं की हत्या कर दी (16 जनवरी 1930 की राज्याज्ञा के द्वारा इस प्रकार के पशुवध पर प्रतिबंध लगाया गया था और इस अपराध के लिए सम्पत्ति जब्त की जा सकती थी और कारावास या देश निकाला की सजा हो सकती थी) या नज़दीक के शहर में जाकर उसे बेच दिया। इसके परिणामस्वरूप 1928 के मुकाबले 1933 में एक तिहाई भेड़, आधे घोड़े और सुअर तथा 54 प्रतिशत कम जानवर रह गए।

कृषि अर्थव्यवस्था पर हमला करने के साथ-साथ परम्परागत कृषक संस्कृति के केंद्र में ऑर्थोडोक्स चर्च के खिलाफ भी तेज अभियान चलाया गया। सभी ऐतिहासिक चर्चों को ध्वस्त कर दिया गया और कई पादरियों को बंदी बना लिया गया। मठ बंद कर दिए गए। हालांकि इनमें से अधिकांश में नमूने के तौर पर कृषि सहकारी समितियां चला रहे थे और हज़ारों भिक्षुओं और मठवासिनियों को साइबेरिया भेज दिया गया। 1930 के अंत तक लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण चर्च बन्द हो चुके थे। कुलक विरोधी अभियान के द्वारा लगभग 1,000,000 किसान परिवार (औसतन प्रति गांव एक परिवार) या लगभग 50 से 60 लाख लोग अपनी ज़मीन और घर से हाथ धो बैठे।

रूस के देहातों में एक वास्तविक गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। बचे हुए पशुधन के रेवड़ और वसंत में होने वाली खेती बीज के अभाव में घोर संकट में थी। मार्च 1930 में स्टालिन ने अपने एक लेख ''डिजी विद् सक्सेस'' में उन्होंने इस ज़्यादती का आरोप अपने अधिकारियों पर लगाया। उसने थोड़े दिन के लिए सामूहिकीकरण अभियान बंद कर दिया और आदेश दिया कि कुलकों को छोड़कर सब लोगों के एकत्र किए पशु उनके मूल मालिकों को लौटा दिए जाएं और इस प्रकार कृषक बाज़ार को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयत्न खत्म हुआ। किसानों ने यह समझा कि अनिवार्य सामूहिकीकरण वापस ले लिया गया है और अधिकांश किसान तीव्रता से सामूहिकीकरण से अलग हो गए। सरकारी आंकड़े के अनुसार 1 मार्च और 1 जून 1930 के बीच सोवियत रूस में सामूहीकृत कृषक परिवारों का प्रतिशत 56 से गिरकर 23 तक पहुंच गया और अगस्त में यह 21.4 रह गया।

कोलखोज के एक नए मॉडल अधिनियम में इसके सदस्यों को एक गाय, भेड़ और सुअर रखने और अपने छोटे व्यक्तिगत खेत पर खुद काम करने के लिए कृषि औज़ार रखने की रियायत दी गई। इन छोटे निजी खेतों से किसानों को आमदनी होती थी, उनका खाना-पीना चलता था और अनाज बेचकर वे अपनी छोटी-मोटी ज़रूरतें पूरी करते थे।

सामूहिकीकरण अभियान थोड़े दिनों के लिए ही शिथिल किया गया था। 1930 में मौसम अनुकूल और फसल बेजोड़ रही। जैसे ही राज्य के भंडारों में अनाज भरा वैसे ही इस बार स्पष्ट निर्देशों के साथ सामूहिकीकरण अभियान दुबारा शुरू कर दिया गया। कोलखोज संगठनकर्ताओं और अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए हज़ारों साम्यवादी और शहरी मज़दूरों को लामबंद करके गांवों में भेजा गया। ग्रामीण जनता को धीरे-धीरे मनाया गया और उन पर मनमाने ढंग से कर लादा गया ताकि वह सामूहिकीकरण में लौट जाएं। 1937 तक कुल फसल क्षेत्र का 86 प्रतिशत कोलखोजों के अधीन आ गया था, 89 प्रतिशत अनाज सामूहिक खेतों में पैदा हुआ और सरकार ने 87 प्रतिशत वसूली इन्हीं खेतों से की।

6.4.5 सामूहिकीकरण की प्रकृति

सामूहिकीकरण को कभी-कभी 'दूसरी क्रांति' भी कहा जाता है क्योंकि इसने किसानों के जीवन को बोल्शेविक क्रांति से भी ज़्यादा प्रभावित किया। किसानों ने इसको अपने आप स्वीकार नहीं किया बल्कि इसे शहरी और सर्वहारा दल के द्वारा जबरदस्ती लादा गया; कहने का तात्पर्य यह है कि यह प्रामाणिक रूप से आरोपित क्रांति थी। सामूहिकीकरण के पहले और बाद किसानों की स्थिति में प्रमुख और आधारभूत अंतर यह था कि एक सामूहिक किसान का सामूहिक खेती से उगाए अनाज और नगदी फसलों पर कोई अधिकार नहीं था। अधिकांश सामूहिक खेत पूर्ववर्ती कम्युन के समान थे और किसानों की हालत लगभग कृषिदासों जैसी हो गई थी।

किसानों को बिना अनुमति खेत छोड़कर जाने का अधिकार नहीं था; कृषकों के मन में यह बात घर करने लगी कि यह सामूहिकीकरण कृषिदास प्रथा का ही नया रूप था। किसान व्यंग्य किया करते थे कि अखिल संघ साम्यवादी दल (रूसी भाषा में वी.के.पी.) ''कृषि दास व्यवस्था'' (*वतोरो क्रेपोस्तनो प्रावो*) की व्याख्या की थी।

सामूहिकीकरण के द्वारा राज्य ने अनाज, आलू और सब्ज़ियों की वसूली बढ़ाई; इससे उद्योगों को कृषक मज़दूर मिले, परंतु इससे पशुधन की हानि हुई; कृषि का उत्पादन जारी रहा और ग्रामीण शहरी लोगों का जीवन स्तर कायम रहा। परंतु इसमें कृषि में किए गए विस्तार से लोगों की बढ़ती मांग पूरी नहीं की जा सकी और इस अर्थ में यह असफल रही।

अनाज उत्पादन, उपज और राज्य वसूली

वर्ष	अनाज उत्पादन मिलियन टन प्रतिहेक्टेयर	उपज क्विंटल	वसूली
1909-13	72.5	6.9	.
1928-32	73.6	7.5	18.1
1933-37	72.9	7.1	27.5
1938-40	77.9	7.7	32.1

स्रोतः ***मोशेलेविन, द मेकिंग ऑफ द सोवियत सिस्टमः एस्सेज इन द सोशल हिस्ट्री ऑफ इन्टरवार रशिया***, लंदनः मेथ्यून, 1985, टेबुल 6.2 पृष्ठ 167

1) कृषि का सामूहिकीकरण किस प्रकार किया गया। दस पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) सामूहिकीकरण अभियान के प्रति किसानों की क्या प्रतिक्रिया हुई? पचास शब्दों में उत्तर दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

6.5 आतंक और शुद्धीकरण

सामूहिकीकरण और औद्योगीकरण के जबरदस्ती लागू करने से सोवियत जनता के जीवन में कोई सुधार नहीं आया बल्कि 'ऊपर से आरोपित क्रांति' नवीनीकरण करके धीरे-धीरे आंतक के राज्य में परिणत हो गई। यह केवल किसानों और पूंजीवाद के बचे के खिलाफ ही नहीं था बल्कि आनेवाले वर्षों में औद्योगिक मज़दूरों और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ भी इसने कार्यवाई की और लोगों को गिरफ्तार किया, मुकदमें चलाए गए और अंततः विरोधियों का सफाया करने वाले और आंतक मचाने वाले खुफिया पुलिस के खिलाफ भी यही कार्य किया गया।

1930 के दशक में स्टालिन की कम से कम तीन राजनैतिक ज़रूरतों की चर्चा इतिहासकारों ने की है। सबसे पहले साम्यवादी दल के भीतर उसकी नीतियों के खिलाफ उठने वाले विरोधी स्वरों और आलोचनाओं को दबाना था। 1933-34 में इसी दबाव के कारण औद्योगीकरण और सामूहिकीकरण अभियान में ढ़ील दी गई, कार्यशील लोगों को रियायतें दी गई और पूर्व विरोधियों से समझौता किया गया। उनकी दूसरी ज़रूरत न केवल विरोधियों को परास्त करना था बल्कि सभी प्रकार के संभावित विरोधों को जड़ से उखाड़ फेंकना था और उन पर आक्रमण करने के साथ-साथ दलीय नेतृत्व की जनतांत्रिक परम्पराओं में निहित आलोचना के स्वर को समाप्त करना था। इसकी परिणति स्टालिन की तीसरी ज़रूरत के रूप में हुई जिसमें उन्होंने एकदलीय शासन व्यवस्था को एकशासक राज्य सत्ता में बदलने का प्रयास किया। अपने इस कार्य के समर्थन में स्टालिन केवल यही तर्क दिया करता था कि वह यह सब कुछ राज्य सत्ता के खिलाफ हो रहे षडयंत्र को रोकने के लिए कर रहा था। उसका कहना था कि इस षड्यंत्र में केवल दलीय संगठन ही नहीं बल्कि क्रांति के बाद के अभिजात्य और संज्ञान जैसे खुफिया पुलिस और सेना भी शामिल थी। बिगड़ती अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और युद्ध का खतरा दिखाकर बताया गया कि शासन खतरे में था परंतु जिन लोगों को मारा गया उनमें से एक भी व्यक्ति को जासूस या षड्यंत्रकारी साबित नहीं किया गया।

6.5.1 चार मुकदमे

1936, 1937 और 1938 में चार मुकदमे चलाए गए जो शुद्धीकरण द्वारा विरोधियों को समाप्त करने के सबसे नाटकीय उदाहरण थे।

1) अगस्त 1936 में 16 लोगों पर चलाए गए मुकदमे में अभियोगकर्ता विशिंस्की द्वारा कामनेव, जिनौविव और अन्य लोगों पर ट्रॉटस्की के साथ षड्यंत्र कर राज्य सत्ता को उखाड़ने और स्टालिन तथा पोलितब्यूरो के अन्य सदस्यों को हटाने का आरोप लगाया गया। आरोपियों ने कथित रूप से अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार किया और कुछ अन्य दक्षिणपंथियों पर आरोप लगाया और प्रतिवादियों को गोली मार दी गई।

2) जनवरी 1937 को 17 लोगों पर चले मुकदमे में पियाताकोव, मोरालोव और राडेक जैसे लोगों पर जापान और जर्मनी से मिलकर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने अपराध स्वीकार किया और उन्हें भी मृत्यु दंड दिया गया।

3) लाल सेना को प्रभावी बनाने वाले मार्शल तूखाचेवेस्की और अन्य सेनाप्रमुखों ने इन मुकदमों की जमकर आलोचना की। मई 1937 में उन्हें और अन्य प्रमुख सेनाध्यक्षों को गिरफ्तार किया गया और उन पर जर्मनी और जापान के साथ मिलकर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया; उन्हें भी गोली मार दी गई।

4) मार्च 1938 में 21 लोगों पर चले मुकदमे में बुखारिन, रीकोव और इगोडा भी शामिल थे। अभियोगकर्ताओं ने यह दावा किया कि विदेशी जासूसी एजेंसियां सोवियत रूस में बुर्जूआ पूंजीवादी राज्य सत्ता की स्थापना के लिए दक्षिणपंथी और ट्रॉटस्की के समर्थकों का एक दल निर्मित करना चाहती थी और सोवियत रूस से गैर रूसी क्षेत्र को अलग कर देना चाहती थीं।

ये बस हिमशैल का उपरी हिस्सा हैं। 1937 और 1938 के पूरे दो वर्षों में सरकार, दल, मज़दूर और सेना और यहां तक कि पुलिस में काम करने वाले लोगों को 'जनता का शत्रु' कहकर गिरफ्तार किया गया और वे जेलों और श्रमिक शिविरों में लापता हो गए। स्टालिन के अलावा लेनिन के पोलित ब्यूरो के सभी सदस्यों पर या तो मुकदमा चलाकर मार दिया गया या दूसरे तरीकों से उनकी मृत्यु हो गई। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री, साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय (कॉमिन्टर्न) के दो भूतपूर्व अध्यक्ष, मज़दूर संगठन के प्रमुख और राजनैतिक पुलिस के दो अध्यक्षों को मृत्युदंड दिया गया।

6.5.2 शुद्धीकरण और साम्यवादी दल

क्रांति के पहले भूमिगत रहकर, गृहयुद्ध और सामूहिकीकरण के युग तथा पंचवर्षीय योजना के दौरान पनपे साम्यवादी नेताओं के समूह को नेस्तनाबूद कर दिया गया। 1941 में जब रूस ने द्वितीय विश्वयुद्ध में हिस्सा लिया तब तक रूसी क्रांति के नेतृत्व से उसके सारे सम्पर्क लगभग टूट चुके थे। इस प्रकार आंतक के राज्य ने पुराने साम्यवादी दल को नष्ट कर दिया जिसे बाद में ख्रुश्चेव के ज़माने में ही फिर से गंभीरतापूर्वक गठित किया जा सका। पुराने साम्यवादी दल के नष्ट हो जाने से स्टालिन की पार्टी, सरकार और देश पर पकड़ मज़बूत हो गई।

6.5.3 शुद्धीकरण और सेना

केवल दल ही ध्वस्त नहीं हुआ बल्कि सेना के बड़े अधिकारियों का भी शुद्धीकरण कर दिया गया। महान शुद्धीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सोवियत सेना के 35 से 50 प्रतिशत

सेनाधिकारियों का सफाया कर दिया गया। सेनाध्यक्ष कार्यालय के जाने माने सदस्य जैसे मार्शल टुखासेवेस्की और ब्लेशर और जेनरल गमारनिक और यामिर को मार दिया गया। उसके अलावा सर्वोच्च युद्ध परिषद के सदस्यों, पांच में से तीन मार्शलों, सोलह में से चौदह सेनाध्यक्षों और सभी एडमिरलों की हत्या कर दी गई। ज़िला के सभी सेना प्रमुखों, रेजिमेंटल कमांडर में से आधे लोगों तथा एक को छोड़कर सभी फ्लीट कमांडर भी प्रभावित हुए।

इन शुद्धीकरण कार्यक्रमों के चलते लाल सेना की देशभक्ति का अपमान हुआ और इससे सेना कमज़ोर हो गई। नाजियों के खिलाफ युद्ध करते समय जितने वरिष्ठ सेना अधिकारी नहीं मारे गए थे उससे ज़्यादा इस शुद्धीकरण कार्यक्रम के दौरान मारे गए।

6.5.4 शुद्धीकरण और सोवियत समाज

1930 के दशक का आतंक घर-घर में प्रवेश कर गया और सोवियत जनता ने बहुत गहराई से इसे अनुभव किया। सब लोग इस बात से सहमत हैं कि 5 प्रतिशत लोगों को जेल में डाल दिया गया था; लगभग अस्सी लाख लोगों को बंदी बनाया गया था जिसमें 10 प्रतिशत लोगों की हत्या कर दी गई। 1938 तक लगभग हर घर से एक व्यक्ति जेल में बंद था। शिक्षित समुदायों में यह अनुपात और भी ज़्यादा था।

1930 के दशक का आतंक सामूहिकीकरण से इस अर्थ में भिन्न था कि यह शहरी जनसंख्या, राजनैतिक नेताओं, सैन्य अधिकारियों तथा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्गों के खिलाफ था। लोगों को इसलिए दंड दिया गया क्योंकि उन पर शक था कि वे सोवियत समाज को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसका निर्धारण उनके सामाजिक वर्गीकरण, सामाजिक उत्पत्ति, राष्ट्रीयता या समूह सदस्यता के आधार पर किया गया। सामाजिक वर्गीकरण लोगों की नियति का आधार बन गया। यह बताना ज़रा मुश्किल है कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितने लोगों को मार डाला गया क्योंकि ये आंकड़ें अभी भी फाइलों में बंद हैं। 1990 में सोवियत अनुसंधानकर्ताओं ने दावा किया कि 1931 और 1953 के बीच सरकारी ट्रिब्यूनल ने लगभग चालिस लाख को हिरासत में ले लिया जिनमें से 20% लोगों को मृत्यु दंड दिया गया परंतु बहुत लोगों की मौत दर्ज नहीं की गई और आंकड़ों में हेर-फेर किया गया, खो गए या नष्ट कर दिए गए। इसलिए ये संख्या निश्चित रूप से सत्य से बहुत दूर है और इनमें आकड़ों को बहुत कम करके बताया गया है।

बोध प्रश्न 3

1) इतिहासकारों के अनुसार 1930 के दशक में स्टालिन की प्रमुख राजनैतिक प्राथमिकताएं क्या थी? पांच पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

.....

.....

.....

.....

2) 1930 के दशक में शुद्धीकरण ने साम्यवादी दल और सेना को किस प्रकार प्रभावित किया? पांच पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

.....

.....

.....

.....

6.6 सारांश

इस इकाई में 1928 और 1941 के बीच की रूसी अर्थव्यवस्था और राजनैतिक व्यवस्था के तीन महत्त्वपूर्ण पक्षों का विवेचन किया गया हैः योजनाबद्ध औद्योगीकरण, कृषि का सामूहिकीकरण और 1930 के दशक का शुद्धीकरण कार्यक्रम। योजनाबद्ध औद्योगीकरण के तहत पांच वर्षों के लिए औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया और व्यवस्थित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। कृषि के सामूहिकीकरण के द्वारा निजी खेतों को एक साथ मिला दिया गया और उन पर आधुनिक ढंग से राज्य के नियंत्रण में खेती की गई। दल के भीतर और बाहर स्टालिन की नीतियों का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ जो रूस की एकदलीय शासन व्यवस्था को एकशासक राज्य व्यवस्था में परिवर्तित करना चाहता था; परिणामस्वरूप 1930 के दशक में विरोधियों का शुद्धीकरण किया गया। इन शुद्धीकरण कार्यक्रमों के तहत पुराने बोल्शेविक, लेनिन के पोलित ब्यूरो के सदस्यों, सेना के कई अधिकारियों और राज्य के अनेक अधिकारियों को मृत्युदंड दिया गया। वस्तुतः जिसने भी स्टालिन की नीतियों से अपनी असहमति जताई उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सामूहिकीकरण में निशाना ग्रामीण जनता को बनाया गया था जबकि 1930 के दशकों के शुद्धीकरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहरी लोगों, सेना के उच्च अधिकारियों और राजनेताओं तथा शिक्षित जनता को निशाना बनाया गया था। यह कहा जा सकता है कि 1930 के दशक की सरकारी नीतियों के लिए रूसी समाज को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी।

6.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) योजनाबद्ध उद्योग में औद्योगिक विकास की दिशा पूर्व निर्धारित होती है और पांच वर्षों के उत्पादन के लिए उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाता है। देखिए भाग 6.3।

2) सोवियत रूस में कम समय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। देखिए उपभाग 6.3.1, 6.3.2 और 6.3.3।

बोध प्रश्न 2

1) नई आर्थिक नीति के अंतर्गत खेती योग्य ज़मीन जो कुलकों (अमीर किसान) के नियंत्रण में थी उसे सामूहिक खेतों के नियंत्रण में ले लिया गया। अब खेती के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता था। देखिए भाग 6.4।

2) हालांकि सभी वर्ग के किसानों ने सोवियत सरकार के सामूहिकीकरण अभियान का विरोध किया परंतु अमीर किसानों ने ज़्यादा विरोध किया क्योंकि उनका नुकसान ज़्यादा होना था। देखिए उपभाग 6.4.4।

बोध प्रश्न 3

1) इस प्रश्न का उत्तर देते समय बताइए कि स्टालिन ने एकदलीय सत्ता से एक शासक सत्ता की ओर बढ़ने के लिए किस प्रकार अपने सभी राजनैतिक विरोधों का शुद्धीकरण कर दिया। देखिए भाग 6.5।

2) शुद्धीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत पुराने साम्यवादी दल का और क्रांति के समय के सैन्य नेतृत्व वर्ग का सफाया कर दिया गया। देखिए उपभाग 6.5.2 तथा 6.5.3।